किसान के हित में नई कृषि प्रणाली

जगदीप सक्सेना

किसानों को जीवनयापन के साधन और निरंतर आय सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एक प्रमुख योजना है जो एक फसल, एक दर आधार पर बहुत कम प्रीमियम पर सभी प्रकार के अनाजों, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह खड़ी फसलों की रोपाई से लेकर फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों तक फसल के पूरे जीवन चक्र के दौरान सुरक्षा प्रदान करती है। अब तक 5.75 करोड़ से अधिक किसानों को इसमें शामिल किया जा चुका है तथा कई अन्य के शामिल होने की उम्मीद है

नवभारत केंद्र सरकार का बड़ा और महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण है जो देश को समृद्ध, स्वस्थ, शिक्षित और स्वच्छ तथा हरे-भरे राष्ट्रों में बदलने के लिए है। हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि मुख्य मुद्दा बना हुआ है क्योंकि यह लगभग 55 प्रतिशत श्रमशक्ति के जीवनयापन का जरिया है तथा राष्ट्रीय जीडीपी में इसका 14 प्रतिशत योगदान भी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी है तथा कई सुधार लागू किए हैं। इसे और बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता जताई है।

नई योजनाओं और प्रोत्साहनों के लिए पर्याप्त सहायता और निधि उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में निरंतर वृद्धि की है जो पिछले बजट की तुलना में 24 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अब 1.87 ट्रिलियन रुपए हो गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान लगभग 274 मिलियन टन के खाद्य उत्पादन नए कार्यक्रमों और नीतियों की सफलता का प्रमाण है जिसमें मेहनती किसानों, प्रगतिशील वैज्ञानिकों, सहायक कर्मचारियों और अन्य हितधारकों का भी योगदान है।

इसके अलावा, वर्ष 2011-14 की तुलना में वर्ष 2014-17 के दौरान मछली उत्पादन और दुग्ध उत्पादन में भी क्रमशः 20 प्रतिशत और 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान कृषि क्षेत्र की कुल वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत थी जिसे 10.4 तक बढ़ाना होगा ताकि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

नयी योजनाओं के जरिए रणनीतिक प्रयास

कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय ने नयी कृषि प्रणालियों और किसानों की समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके नए भारत के दृष्टिकोण को अमल में लाने के लिए सात-बिंदुओं वाली रणनीतिक योजना बनाई है। रणनीतिक योजना विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत चार-खंड की रिपोर्ट का हिस्सा है जो किसानों की आय दोगुनी करने के तरीकों और साधनों की विस्तार से व्याख्या करती है। रणनीतिक योजना का लक्ष्य विशेष रूप से किसानों की औसत आय को 2015-16 के 96,703 रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 तक 193,400 रुपए करना है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस अवधि के दौरान 1,486 ट्रिलियन रुपए (2004-05 के मूल्यों पर) के संचयी निजी और सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता होगी। यह रणनीति कुल मिलाकर फसलों का उत्पादन बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और कटाई के बाद होने वाले नुकसानों को कम करने तथा कृषि बाजार के सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है। रिपोर्ट बताती है कि अंतिम प्रसंस्करण सुविधाएं, फसल बीमा के जरिए जोखिम कम करना और आपदा से राहत तथा बागवानी एवं दुग्ध उत्पाद जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देना आदि प्राथमिकता में हैं।

सरकार बूंद दर बूंद, *अधिक फसल* अभियान के तहत पानी के उपयोग की

लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के पूर्व मुख्य संपादक हैं। ईमेलः jgdsaxena@gmail.com

बूंद दर बूंद, अधिक फसल
लघु सिंचाई के अधीन दुगुना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- **4510.55 करोड़ रुपये जारी**
- **ड्रिप तथा स्पिंकलर सिंचाई वाले क्षेत्रफल में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी**

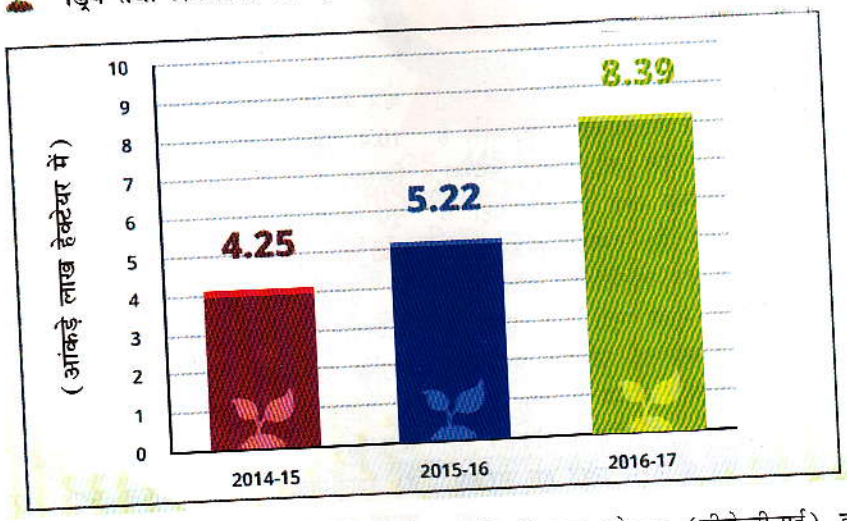

कुशलता को बढ़ाने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास कर रही है। यह अभियान विशेष रूप से माइक्रो-सिंचाई तकनीकों के जरिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने पर ध्यान देता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत किए गए प्रयासों के कारण माइक्रो-सिंचाई के तहत क्षेत्र 2013-14 में 4.3 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2016-17 में 8.3 लाख हो गया है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस (2017) के अपने संबोधन में बताया है कि पीएमकेएसवाईके तहत 30 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 50 परियोजनाओं का काम जारी है।

सरकार की विशिष्ट मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को खेती की लागत कम करने में मदद कर रही है क्योंकि यह योजना रसायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग सुनिश्चित करती है तथा सतत आधार पर मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाती है। देश भर में खेतों की मिट्टी के व्यापक विश्लेषण के आधार पर अब तक किसानों को 7.1 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) का लक्ष्य जैविक कृषि के क्षेत्र को बढ़ाना है क्योंकि यह खेती की लागत कम होने और जैविक उत्पादों का अधिक मूल्य मिलने के कारण किसानों को अधिक आय प्राप्त होना सुनिश्चित करती है। वाणिज्यिक स्तर पर जैविक खेती अपनाने के लिए क्लस्टर निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। अब तक, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से 9,100 से अधिक क्लस्टर बनाए गए हैं जो जैविक उत्पादों को एकत्र करने और संभावित बाजारों तक पहुंचाने में भी सहायता करते हैं।

किसानों को जीवनयापन के साधन और निरंतर आय सुनिश्चित करने के लिए *प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना* (पीएमएफबीवाई) एक प्रमुख योजना है जो *एक फसल, एक दर* आधार पर बहुत कम प्रीमियम पर सभी प्रकार के अनाजों, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह खड़ी फसलों की रोपाई से लेकर फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों तक फसल के पूरे जीवन चक्र के दौरान सुरक्षा प्रदान करती है। अब तक 5.75 करोड़ से अधिक किसानों को इसमें शामिल किया जा चुका है तथा कई अन्य के शामिल होने की उम्मीद है क्योंकि इस

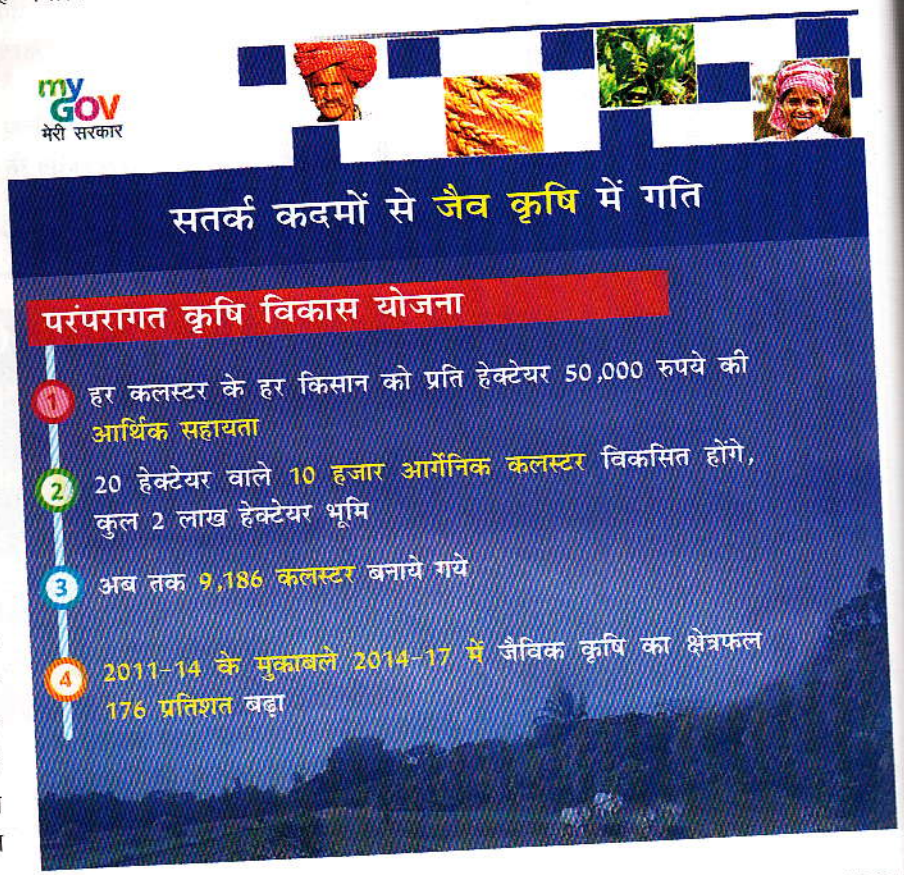

वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए तीन वर्षीय रूपरेखा

- ग्रामीण बीज कार्यक्रम को 30,000 गांवों से बढ़ाकर 60,000 गांवों तक फैलाया जाएगा तथा पंचायत स्तर पर 500 बीज उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- स्थानीय उद्यमियों के जरिए मिट्टी की जांच के लिए 1,000 लघु प्रयोगशालाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
- नाबार्ड के जरिए 5,000 करोड़ रुपए के निर्धारित कॉर्पस को प्रचालनरत किया जाएगा तथा 4.8 हेक्टेयर भूमि को माइक्रो-सिंचाई के तहत लाया जाएगा।
- 2020 तक तीन मिलियन हेक्टेयर को शामिल करने के लिए दालों और तिलहनों के लिए चावल की परती भूमि के उपयोग के जरिए खेती की गहनता को एक मिलियन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा।
- कटाई के बाद की अवसंरचना को मजबूत करने के लिए पांच लाख एमटी कोल्ड स्टोरेज, 1,000 भंडारण स्थल और 150 राइनिंग चैंबर स्थापित किए जाएंगे।
- 350 कृषक उत्पादक संगठनों के जरिए 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि में जैविक कृषि की जाएगी।
- 585 कृषि बाजारों को ई-नाम प्लेटफार्म से जोड़ा जाएगा।
- अल्पावधि ऋणों को वर्तमान में 43 प्रतिशत से बढ़ाकर 2018-19 तक 50 प्रतिशत करके छोटे और सीमांत किसानों को अधिक मात्रा में शामिल करना।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित बीमा योजना के तहत शामिल कुल फसल क्षेत्र को 2017-18 और 2018-19 में बढ़ाकर क्रमशः 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत करना।
- मार्च 2018 तक 16,000 से लेकर 50,000 गांवों से अधिक मात्रा में एकमुश्त दूध इकट्ठा करके दूध अधिप्राप्ति अवसंरचना को सुदृढ़ करना।
- नील क्रांति को बनाए रखने के लिए मछलीपालन को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तर्ज पर राष्ट्रीय मवेशी विकास एजेंसी का गठन।
- उपज के स्तर को बढ़ाने तथा फसलों को विपरीत स्थितियों का सामने करने के योग्य बनाने के लिए जीनोमिक्स जीन संशोधन प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास।
- पोषण भोजन (प्रोटीन, जिंक, विटामिन-ए और एंटी-ऑक्सीडेंट) के लिए जैव-सुदृढ़ीकरण में अनुसंधान एवं विकास
- पशुओं के लिए ताप सहन करने वाली दवाइयों का विकास। ❑

योजना का लक्ष्य शामिल किए गए फसल क्षेत्र को 2016-17 में 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017-18 में 40 प्रतिशत करना है। इसके साथ ही यह योजना कृषि में निवेश को बढ़ावा दे रही है और उसे आकर्षित कर रही है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अधिक बाजार मूल्य का मिलना सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) नामक एक नई पहल व्यापार और लेन-देन के लिए साझा ई-प्लेटफार्म पर 13 राज्यों की 410 मंडियों को एकीकृत करके इस मुद्दे का समाधान कर रही है। अब तक 69 मदों के लिए व्यापार संबंधी मानदंड निर्धारित किए जा चुके हैं और 45 लाख से अधिक किसानों ने स्वयं को ई-नाम प्लेटफार्म पर पंजीकृत कराया है। यह सुधार मजबूरन बिक्री और बिचौलियों को हटाकर किसानों की आय को बढ़ाने में सफल रहा है। अतिरिक्त प्रभाव के रूप में, मदों का थोक मूल्य सूचकांक बढ़ रहा है और विशेषज्ञों के अनुसार, फसलों की कीमतों में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी किसानों की आय को 9.1 प्रतिशत बढ़ाती है। तथापि, किसानों द्वारा प्राप्त की जाने वाले कीमतों को बढ़ाने तथा परिणामस्वरूप किसानों की आय बढ़ने के काफी अवसर मौजूद हैं। लेकिन किसानों की आय पर इसका वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए इन योजनाओं और कार्यक्रमों को समय-बद्ध तरीके से लागू करना होगा।

अधिक लाभ के लिए उत्पादकता बढ़ाना

हाल में, नीति आयोग ने *किसानों की आय दोगुनी करना* विषय पर नीतिगत दस्तावेज प्रस्तुत किया जो मूलभूत स्तर पर कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना के बारे में विस्तार से बताता है। यह दस्तावेज प्रति इकाई भूमि की उत्पादकता तथा इस प्रकार खेत के उसी टुकड़े से किसानों की आय बढ़ाने में सिंचाई और नई प्रौद्योगियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। आक्रामक विस्तार तंत्र और किफायती मूल्यों पर बीमा की आपूर्ति होने से किसानों द्वारा उच्च पैदावार वाली नई और उन्नत फसलों को अपनाया जा रहा है।

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) का लक्ष्य जैविक कृषि के क्षेत्र को बढ़ाना है क्योंकि यह खेती की लागत कम होने और जैविक उत्पादों का अधिक मूल्य मिलने के कारण किसानों को अधिक आय प्राप्त होना सुनिश्चित करती है। वाणिज्यिक स्तर पर जैविक खेती अपनाने के लिए क्लस्टर निर्माण हेतु किसानों को प्रेरित किया जा रहा है।

देश के शीर्ष अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने उत्पादकता को नए स्तर पर ले जाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 600 प्रकार की उन्नत फसलों का विकास किया है। इसके साथ ही, उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए खेतों में नई कृषि प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रचार करना आवश्यक है। उपग्रही खेती, एकीकृत खेती, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियां और संरक्षित खेती कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें काफी क्षमता और संभावना है। इसी प्रकार भूमि को समतल करने के लिए लेजर तकनीक, सटीक बीजरोपक और बुआई मशीन जैसी नई मशीनरी और आधुनिक कृषि पद्धतियां जैसे एसआरआई (चावल गहनता प्रणाली), सीधे रोपे गए धान, जीरो टीलेज,

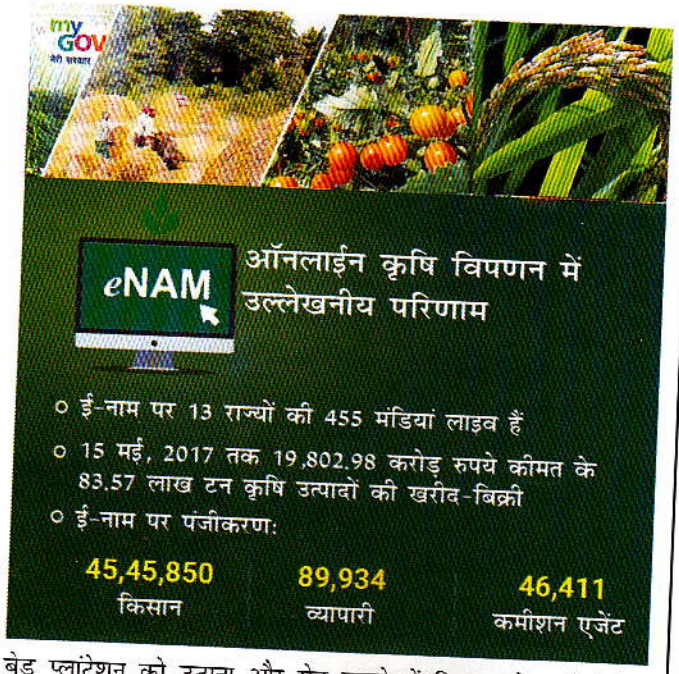

बेड प्लांटेशन को उठाना और मेढ़ बनाने में किए जाने वाले निवेश में भी आकर्षक लाभ की संभावना है जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है।

भूमि की प्रति इकाई आय को बढ़ाने के लिए फसल की गहनता को बढ़ाना भी प्रौद्योगिकीय रूप से एक अच्छा विकल्प है। सिंचाई सुविधाओं और नई तकनीकों की उपलब्धता के साथ ही किसानों के लिए मुख्य फसलों (खरीफ और रबी) के बाद छोटी अवधि की फसलें उगाना संभव हो गया है। इसी प्रकार, लाभ को बढ़ाने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल का विकास किया गया है। ये मॉडल विपरीत मौसम में भी अधिक स्थायी आमदनी प्रदान करते हैं। उच्च मूल्य वाली फसलों (फल, सब्जियां, रेशे, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे) की विविधता भी किसानों की आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करती है। अन्य संबद्ध उद्यमों की विविधता के जरिए भी किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है जैसे वनरोपण, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण आदि। हाल के समय में सरकार द्वारा उठाए गए कदम संबद्ध और गैर-कृषि क्षेत्रों में बेहतर आय के लिए कृषक समुदाय के कौशल को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

नया दृष्टिकोण

पहले के समय में, सरकार का दृष्टिकोण और रणनीति मुख्यत: खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना रहा है। बाद में नीति निर्माताओं ने किसानों की आय बढ़ाने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने की जरूरत को महसूस किया। पहले कदम के तौर पर, भारत सरकार ने 2015 में कृषि मंत्रालय का नाम बदल कर कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय कर दिया। तब से भारत सरकार विभिन्न सुधारों, नीतियों और पहलों के जरिए 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की कोशिशों में लगी हुई है। तदनुसार, नये दृष्टिकोण का लक्ष्य अनाज की कमी को दूर करना तथा किसानों और गैर-कृषि कार्यों में संलग्न व्यक्तियों की आय में समानता लाना है। अपने नए दृष्टिकोण के साथ भारतीय कृषि क्षेत्र नवभारत के सपने को पूरा करने में जुट गया है। ❑

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के नि:शुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

डॉ. विजय अग्रवाल की पुस्तक

'आप IAS कैसे बनेंगे'

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक 'चलता-फिरता कोचिंग संस्थान' है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

YH-655/5/2017